VISION IAS

www.visionias.in

06 AUG 2022

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 2212)

Name of Candidate	Ishwar lal gurjar		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	1295818
Center	Dehli	Date	6-08-2022

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI**
   इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. **All questions are compulsory.**
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न / भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

1. What do you understand by 'constitutionalism'? Highlight various ways in which the Indian Constitution underscores this principle. **(150 words) 10**

'संविधानवाद' से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में इस सिद्धांत को रेखांकित करने वाले विभिन्न उपबंधों पर प्रकाश डालिए।

संविधानवाद उस वैधानिक अवधारणा को कहते है जब संविधान द्वारा किसी सरकार को नियमों एवं कानूनों द्वारा सीमित किया जाता है। जैसे - अनुच्छेद-13 संसद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है।

भारतीय संविधान में इस सिद्धांत को रेखांकित करने वाले निम्नलिखित उपबंध है -

① मौलिक अधिकार - अनु. 12 से 35 तक, सरकार के खिलाफ नागरिकों को स्वतंत्रताओं, समानता और संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

② लिखित संविधान - भारत में लिखित संविधान सरकार को सीमित करता है। सरकार संविधान की मूल भावना का उल्लंघन नहीं कर सकती है।

③ स्वतंत्र न्यायपालिका - न्यायपालिका संविधान की व्याख्याकार है। यह कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा द्वारा नियंत्रण स्थापित करती है।

(4) संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की मूल विशेषताओं की अवधारणा भी संविधानवाद की पोषक है।

(5) शक्तियों का पृथक्करण - अनु. 246 में 7वीं अनुसूची के द्वारा केन्द्र और राज्यों में शक्तियों का बँटवारा तथा सरकार के तीनों अंगों में 'चेक एंड बैलेंस' की स्थिति

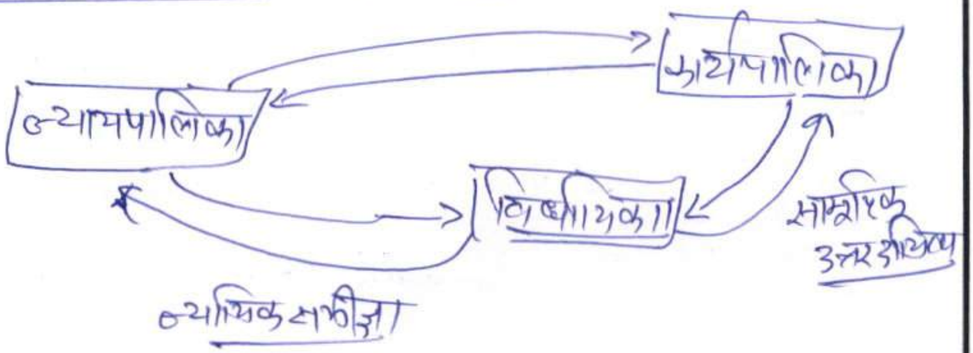

अतः हम कह सकते हैं कि भारत में संविधानवाद संविधान एवं सरकार की कार्यप्रणाली दोनों स्तरों पर विद्यमान है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. The Competition Commission of India (CCI) effectively reflects a shift from the era of Licence Raj to a conducive regulatory ambience for enhancing consumer welfare by encouraging competition in the market. Discuss.

(150 words) 10

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके उपभोक्ता कल्याण को बढ़ाने के लिए लाइसेंस राज के युग से एक अनुकूल नियामकीय परिवेश में स्थानांतरण को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है। चर्चा कीजिए।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम -2002 द्वारा CCI की स्थापना 'MRTP Act -1969' की जगह बाजार में प्रतिस्पर्धा अवरोधों को हटाने एवं उपभोक्ता कल्याण को बढ़ावा देने हेतु लाया गया है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की एक अनुकूल नियामकीय परिवेश निर्माण में भूमिका —

1. प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में CCI का अहम योगदान है। यह प्रभुत्ववादी एवं एकाधिकार वाली गतिविधियों को रोकता है।
   eg - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जुर्माना
2. अप्रतिस्पर्धी डिलस एवं धोखाधड़ी पर निगरानी
   eg - BCCI पर IPL फ्रैन्चाईजी में फ्राड पर जुर्माना लगाना।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. छोटे उद्यमों एवं उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना।

eg- google के विज्ञापन पर एकाधिकार पर कार्यवाही करना।

4. प्रतिस्पर्धा (↑) → गुणवत्ता (↑) → स्वस्थ बाजार प्रणाली

5. उपभोक्ताओं को सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाधित हो यह सुनिश्चित करना

हालाँकि CCI पर पक्षपात (जैसे - रिलायंस जिओ और एयरटेल मामले) एवं स्वतंत्र नियामकों की कार्य प्रणाली (जैसे - RBI, SEBI) में दखल के आरोप लगते रहे हैं लेकिन उसके बावजूद CCI ने लाईसेंस राज प्रणाली को समाप्त कर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी बाजार की स्थापना में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. Mention various initiatives taken for online delivery of judicial services in India. Also, discuss the challenges faced in their implementation.
(150 words) 10

भारत में न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन प्रदायगी के लिए प्रारंभ विभिन्न पहलों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, उनके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

Covid-19 महामारी के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों को ऑनलाइन (वीडियो-कान्फ्रेंसिंग) मुकदमों की सुनवाई करने के निर्देश दिए जिससे न्यायिक प्रणाली का आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी करण तेजी से हुआ।

प्रारंभ विभिन्न पहलें निम्नानुसार है-

1. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड - द्वारा विभिन्न विभागों के मध्य डाटा के संग्रह, संरक्षण, भंडारण एवं प्रसंस्करण की सुविधा।

2. ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना द्वारा अदालतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, उपकरण एवं अवसंरचना विकास पर बल दिया।

3. सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति - की सिफारिशों के आधार पर उच्च एवं अधीनस्थ न्यायालयों को सलाह एवं निर्देशन।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. "जस्टिस क्लॉक" - गुजरात हाईकोर्ट द्वारा मुकदमों को ट्रैक करने के लिए निर्मित प्रणाली

5 SUVAC एवं SUPACE द्वारा उच्चतम न्यायालय में अनुवाद, मुकदमों की लिस्टिंग सुविधा

6 न्यायिक सेवा-केन्द्र द्वारा मुकदमों की ड्राफ्टिंग एवं विषय वस्तु तैयार करना

चुनौतियाँ - (क) अवसंरचनात्मक चुनौतियाँ

eg- 74% अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था नहीं

eg- इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्प्यूटर, अन्य उपकरण

(ख) कौशल एवं जागरूकता - न्यायाधीशों एवं वकीलों के पास ई-तकनीक का कौशल नहीं तथा अभियोगियों में जागरूकता नहीं।

(ग) साइबर सुरक्षा - संवेदनशील डाटा की गोपनीयता

(घ) डिजीटल डिवाइड, धोखाधड़ी, फेक गवाही की दिक्कत आना, न्यायिक सेवाओं की ऑनलाइन उपायमी को वैकल्पिक रूप से अपनाते हुए इसमें सुधार की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. Bring out the similarities and differences in the Bill of Rights in the Constitution of the United States and Fundamental Rights in the Constitution of India. **(150 words) 10**

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में उपबंधित बिल ऑफ राइट्स और भारत के संविधान में मूल अधिकारों के मध्य समानताओं और भिन्नताओं को रेखांकित कीजिए।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने संविधान में 10वें संशोधन द्वारा बिल ऑफ राइट्स को जोड़ा जो इंग्लैण्ड के मैग्ना कार्टा से प्रेरित था।

समानताएँ - 1. संवैधानिक संरक्षण दोनों को ही प्राप्त है। भारत में यह अनु० 32 के तहत 'संवैधानिक उपचार' के अधिकार रूप में।

2. भारत में अनु० 21 में गरिमापूर्ण जीवन की बात है तो अमेरिका में भी जीवन का व्यापक अधिकार है।

3. दोनों ही प्राकृतिक न्याय एवं मानवाधिकारों के व्यापक समूह से सुसंगत है।

भिन्नताएँ - (क) 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' भारत में अपनाई गई जबकि अमेरिका ने विधि की सम्यक प्रक्रिया को अपनाया।

(ख) प्रेस की स्वतंत्रता - अमेरिका में अलग से उल्लेखित जबकि भारत में अनु. 19(1)(a) में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(ग) हथियारों की स्वतंत्रता - अमेरिका में हथियार रखना मौलिक अधिकार है जबकि भारत में नहीं है।

(घ) सम्पत्ति का अधिकार अमेरिका में अभी भी एक मूल अधिकार है, भारत में अनु० 300(a) के तहत एक संवैधानिक अधिकार है।

(ङ) अमेरिका में मूल अधिकार संशोधन द्वारा जोड़े जबकि भारत में मूल संविधान का भाग है।

अतः अमेरिकी संविधान में 'बिल ऑफ राइट्स' ~~मानना~~ उसके संघवादी चरित्र एवं कठोर संविधान की प्रकृति के अनुरूप है। भारत के मूल अधिकार समानता के बावजूद भारतीय शासन अनुरूप है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. It is often argued that the implementation of The Forest Rights Act (FRA), 2006 has so far been tardy and ineffectual. Discuss. **(150 words) 10**

प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि अभी तक वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का कार्यान्वयन धीमा और निष्प्रभावी रहा है। चर्चा कीजिए।

अनुसूचित जनजाति एवं पारम्परिक वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 वन वासियों को आजीविका, निवास, लघु वनोपज के सामूहिक एवं व्यक्तिगत अधिकार प्रदान करता है।

कार्यान्वयन धीमा और निष्प्रभावी रहने के कारण

1. राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव - FRA-2006 द्वारा वनवासियों को वनभूमि आंवटन एवं आजीविका अधिकार देने में स्थानीय राजनीति की अनिच्छा।

2. प्रशासन की उदासिनता - वन नौकरशाही अपने अधिकारों को कम नहीं करना चाहती तथा स्थानीय प्रशासन का टाल मटोल रवैया

3. समन्वय का अभाव - FRA-2006 जनजातीय मंत्रालय में आता है जिसका पर्यावरण, राजस्व विभागों के साथ समन्वय का अभाव है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. वन भूमि का स्थानांतरण - सरकार द्वारा कोयला खनन, बांध निर्माण आदि विकासात्मक कार्यों में वन भूमि को स्थानांतरित किया।

5. कौशिल एंव लम्बित कार्यवाही के कारण वन निवासियों को अधिकार बहुत कम मिले तथा अधिकार मामले लम्बित है। मुकदमेबाजी इसे खर्चीला बनाती है।

आगे की राह - FRA-2006 की मूल भावना को साकार करने के लिए ग्रामसभाओं का सशक्तिकरण, फेक लाभार्थियों की पहचान एंव व्यापक जनसुनवाई कैम्पों का आयोजन करने की जरूरत है।

अतः आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का अधिकार देने के लिए FRA-2006 की भावनाओं के साथ न्याय होना जरूरी है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Explain the rationale behind the creation of a Social Stock Exchange in India. Do you think this move would boost social impact investing in the country? **(150 words) 10**

भारत में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के सृजन के पीछे निहित तर्क की व्याख्या कीजिए। क्या आपको लगता है कि इस कदम से देश में सामाजिक प्रभाव वाले निवेश को प्रोत्साहन प्राप्त होगा?

हाल ही में SEBI ने 2021 में 'सोशल स्टॉक एक्सचेंज' की स्थापना की अनुमति प्रदान कर सामाजिक उद्यम की ओर एक बड़ा कदम उठाया है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर गैर-लाभकारी एवं 'गैर-सरकारी संगठनों' को सूचीबद्ध किया जाता है ताकि वह फंडिंग, निवेश जुटा सके।

पीछे निहित तर्क

* सामाजिक उद्यम को बढ़ावा देना
* सामाजिक पूंजी का निर्माण
* NPO में निवेश बढ़ना
* उद्यमों के सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देना
* सरकार पर बोझ कम करना
* व्यापक सेवा वितरण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सामाजिक प्रभाव वाले निवेश में निम्नानुसार बनाना होगा —

(क) उद्यमों की सामाजिक प्रभाव का बेहतर आकलन एवं विश्लेषण होगा।

(ख) निवेश हेतु व्यापक पूँजी

(ग) उद्यमों की सामाजिक जिम्मेदारी पर बेहतर निगरानी होगी।

(घ) सामाजिक उत्तरदायित्व का बेहतर निर्वहन

अतः सोशल स्टॉक एक्सचेंज भारत में सरकार के लिए एक आगामी अवसर एवं विकल्प होगा जिससे सेवा वितरण बेहतर हो पायेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. The National Digital Health Mission (NDHM) has the potential to bring a new revolution in India's health sector in multiple ways. Explain.

(150 words) 10

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्रक में कई तरह से एक नई क्रांति लाने की क्षमता है। व्याख्या कीजिए।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 'PM जन आरोग्य योजना' के तहत 'आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन' के रूप में कि गई।

उद्देश्य —

* नागरिकों को यूनिक हेल्थ आईडी (UHID)
* डिजी-डॉक्टर एवं ई-फार्मेसी की सुविधा होगी।
* ऑनलाइन स्वास्थ्य रिकॉर्ड रहेगा
* टेली-मेडिसिन संभव होगा।
* ऑनलाइन मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना
* स्वास्थ्य सेवा।

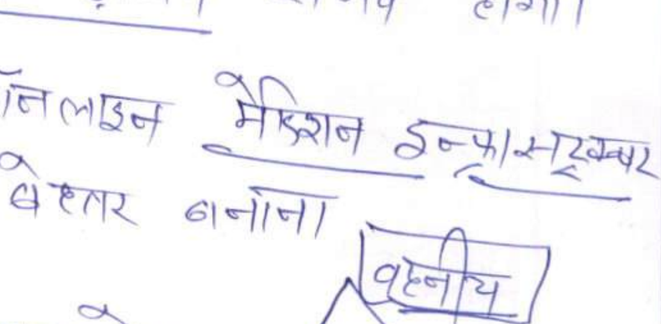

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(लाभ) -> 1. सेवा वितरण प्रभावी बनेगा।
eg - स्वास्थ्य रिकॉर्ड द्वारा अनावश्यक जाँच से (बार-बार) बचाव

2. बीमा कवरेज बेहतर होगा।
eg - क्लेम पास कराने की कागजी कार्यवाही में कमी

3. स्वास्थ्य सेवा में बेहतर निगरानी, नीति-निर्माण एवं मूल्यांकन तंत्र

4. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो अभी 65% है; कम होगा।

5. दुर-दराज तक सेवा पहुँचेगी

6. सर्वोच्च वैश्विक प्रथाओं का लाभ

अत: ABHM भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है यदि अवसंरचना, डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट कनेक्टिविटी को कम कर सके।

—x—

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. While participation of private sector in the higher education system of India is a necessity, it creates issues that need careful redressal. Discuss.
(150 words) 10

हालांकि भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक अनिवार्यता है, लेकिन यह ऐसे मुद्दे उत्पन्न करता है जिनका सावधानीपूर्वक निवारण किए जाने की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में 'व्यापकता', 'गुणवत्ता' एवं 'वहनीयता' की समस्याएँ अन्तर्निहित है जिनका समाधान सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र मिलकर निकाल सकते है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी अनिवार्यता के रूप में-

(क) भारत में '31 हजार' से अधिक निजी कॉलेज है जो कुल उच्चतर शिक्षा का लगभग - 40% भार वहन करते है।

(ख) भारत में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (GER) बहुत कम (लगभग -25%) है जिसे बढ़ाकर 'नई शिक्षा नीति'-2020 में 50% करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी अनिवार्य है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की खस्ता हालत – सार्वजनिक क्षेत्र के कॉलेजों में शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ के 30% पद खाली हैं। अवसंरचना की गरीब स्थिति के कारण मांग पूर्ति नहीं होती।

(घ) गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी निजी क्षेत्र की उपस्थिति जरूरी है।

निजी क्षेत्र सम्बंधी चुनौतियाँ

- (I) वहनीयता – ऊँची फीस, अन्य शुल्क
- (II) गुणवत्ता में अनिश्चितता – शुरु में ठीक बाद में खराब
- (III) शिक्षा का व्यापारीकरण
- (IV) नियमन का अभाव
- (V) बदलता पाठ्यक्रम एवं शैक्षिक प्रणालियाँ

निवारण –
- नई शिक्षा नीति में 100% FDI की
- विदेशी विश्वविद्यालयों के कैम्पस खोलना
- PPP मोड की शिक्षा प्रणाली लागू करना
- 'विद्यादान' जैसी स्कीम द्वारा
- सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को बेहतर करना / समग्र शिक्षा अभियान

अतः भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन करते हुए, नियामक ढाँचा बनाने की जरूरत है।

9. Highlighting the significance of Central Asia for India, discuss the challenges in strengthening the Indo-Central Asian relationship. (150 words) 10
भारत के लिए मध्य एशिया के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, भारत-मध्य एशियाई संबंधों को मजबूत करने के समक्ष विद्यमान चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

मध्य एशिया में पाँच राष्ट्र प्रमुखतः शामिल हैं- कजाखिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इत्यादि। इनके साथ भारत का सभ्यतागत, ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं व्यापारिक (रेशम मार्ग) रिश्ता रहा है।

भारत के लिए महत्व

* ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से eg- TAPI पाइपलाइन
* कजाखिस्तान के यूरेनियम एवं प्राकृतिक गैस का खनन।
* सुरक्षा की दृष्टि से eg- कश्मीर में आतंकवाद
* अफगानिस्तान में 3B $ का निवेश की सुरक्षा
* सामरिक दृष्टि से eg- उत्तर-दक्षिण गलियारा
* रूस तक कनेक्टिविटी
* व्यापारिक दृष्टि से।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

चुनौतियाँ →

(*) राजनीतिक अस्थिरता — ए- अफगानिस्तान में तालिबान

(*) चीन का बढ़ता प्रभुत्व
ए. BRI परियोजना में मध्य एशिया के देश शामिल है।
ए- SCO में चीन का नेतृत्व

(*) पाकिस्तान की अस्थिरता — भारत के लिए PoK को पार करना मुश्किल है।

(*) आतंकवाद, उग्रवाद का भारत में आयात होता रहना

(*) विश्व राजनीति का अखाड़ा बनना

अतः भारत के लिए मध्य एशिया अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत को TAPI गैस पाइपलाइन, चाबहार बंदरगाह, उत्तर-दक्षिणी परिवहन गलियारा जैसी योजनाओं को जल्द पूरा कर अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

10. Discuss the role that the Indian diaspora can play in the making of "Aatmanirbhar Bharat" (self-reliant India). Also, mention the challenges in this regard. **(150 words) 10**

"आत्मनिर्भर भारत" के निर्माण में भारतीय डायस्पोरा द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इस संबंध में विद्यमान चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए।

'आत्मनिर्भर भारत' के योगदान में भारत के 30 मिलियन भारतीय डायस्पोरा (OCI+PIO) का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है।

भारतीय डायस्पोरा की भूमिका

1. **आर्थिक भूमिका** - भारत को वर्ष 2021 में 87 B $ का रेमिटेंस प्राप्त हुआ जो हमारे भुगतान संतुलन (BOP) में महत्वपूर्ण

2. भारतीय उत्पादों की वैश्विक माँग को बढ़ावा देते है eg- भारतीय मसाले. eg- भारतीय फिल्में जिससे भारत का निर्यात बढ़ता है।

3. NRI द्वारा भारत में FPI एवं FDI

4. **सांस्कृतिक भूमिका** - भारतीय डायस्पोरा अपने साथ सांस्कृतिक मूल्यों, प्रथाओं, त्योहारों (दीवाली)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

को सम्पूर्ण विश्व में प्रसारित करता है।
eg- अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिवाली मनाना
eg- कनाडा के PM द्वारा बसंत पंचमी

4. सामरिक सम्पत्ति - भारतीय डायस्पोरा विदेशों में भारत के लिए दबाव समूह का कार्य जो वैश्विक रूझानों को भारत की तरफ मोड़ता है। eg- इंग्लैण्ड के PM ऋषि सुनक
eg- USA की उपराष्ट्रपति

चुनौतियाँ → (क) बढ़ता संरक्षणवाद - USC द्वारा H,B, वीजा पॉलिसी बदलाव
(ख) प्रवासियों पर हमले एवं बढ़ती भेदभावपूर्ण घटनाएँ eg- कैनाडा की घटना
(ग) भारतीय नागरिकता छोड़ना = गृह मंत्रालय के अनुसार 2021 ई. में 1.63 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी
(घ) ब्रेन ड्रेन की समस्या

आगे की राह - भारतीय डायस्पोरा भारत के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है इसलिए भारत सरकार OCI कार्ड धारक, देखो अपना देश जैसी योजना चला रही है

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. A critical appraisal of the outcomes of the 74th Constitutional Amendment Act underlines the need for second-generation reforms to strengthen decentralisation of urban local governance in India. Discuss. **(250 words) 15**

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के परिणामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन भारत में शहरी स्थानीय शासन के विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करने हेतु दूसरी-पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। चर्चा कीजिए।

74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय प्रदान किए लेकिन वर्तमान में बढ़ता केन्द्रीकरण, शहरीकरण नए (दूसरी पीढ़ी) सुधारों की मांग कर रहे हैं।

अधिनियम के परिणामों में कमियाँ

1. राज्य सरकारों ने शहरी निकायों को '18 विषयों' का स्थानांतरण नहीं किया
2. शहरी निकायों में राजनीतिकरण बढ़ना
3. वित्तीय चुनौतियाँ — वित्त आयोग (राज्य) द्वारा वित्त हस्तांतरण बहुत कम तथा स्वयं की राजस्व आय नहीं; कर लगाने का अधिकार नहीं होना
   eg - जयपुर महापौर खोखला

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. समन्वय चुनौतियों का अभाव –
Eg- महापौर की चुनाव पद्धति अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होना।

5. बढ़ता शहरीकरण ने निवास, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति को बढ़ा दिया। शहरी निकायों के संसाधन सीमित एवं मांग असीमित है।

6. शहरी निकायों की त्रिस्तरीय व्यवस्था का उल्लंघन

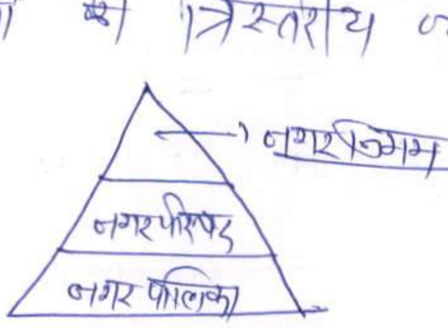

विकेन्द्रीकरण को सुदृढ़ करने हेतु दूसरी पीढ़ी के सुधार – निम्नानुसार है।

(क) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार 2050 तक 50% आबादी शहरों में निवास करेगी अतः निवास, पेयजल, जलापूर्ति

विद्युत, सफाई इत्यादि हेतु नगर निकायों का सुदृढीकरण आवश्यक है। इसके लिए निकायों को मानव संसाधन, कुशल नीति, संधान प्रदान करना। eg- स्मार्ट सीटी eg- हृदय योजना

(ख) राज्य वित्त आयोग द्वारा अधिक राजस्व हस्तांतरण eg- जनसंख्या के आधार पर

(ग) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुदानों को कार्य निष्पादन से लिंक्ड करना

(घ) प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना [स्वास्थ्य सूचकांक, नगरपालिका सूचकांक

(ङ) स्वंय की राजस्व आय सृजन करना eg- मनोरंजन कर GST से निकायों को

अतः बढ़ती शहरी आबादी के सशक्तिकरण हेतु राज्यों को अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण शहरी निकायों के साथ संतुलित होकर करना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. It is argued that unchecked and rampant exercise of the power to insert laws in the Ninth Schedule results in undermining of Constitutional supremacy and creation of Parliamentary hegemony. Do you agree? Justify your stand with logical arguments. (250 words) 15

यह तर्क दिया जाता है कि नौवीं अनुसूची में विधियों को सम्मिलित करने की शक्ति के अनियंत्रित और व्यापक स्तर पर प्रयोग से संवैधानिक सर्वोच्चता में कमी और संसदीय आधिपत्य का सृजन होता है। क्या आप सहमत हैं? उचित तर्कों के साथ अपने मत की पुष्टि कीजिए।

9वी अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनु० 31(B) मे जोडा गया। इसका मकसद भूमि सुधारो के कानूनो को न्यायिक मुकदमेबाजी से बचाना था लेकिन वर्तमान मे इसमे -284 अधिनियमो को जोडकर इसका दुरुपयोग किया गया

संवैधानिक सर्वोच्चता मे कमी और संसदीय आधिपत्य का सृजन के रूप मे 9वी सूची —

→(क) स्वतंत्र न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम करती है जो कि संविधान का बुनियादी ढांचा है।
eg- आई- आर- कोएल्हो वाद

→(ख) संसद को बिना रोकटोक की विधायी शक्ति देती है जो शक्ति पृथक्करण का

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

सिद्धान्त का उल्लंघन है।

(ग) राजनीतिकरण - होने से इस अनुसूची का दुरुपयोग किया गया जिसस गैर-जरूरी एक्टस् को भी इसमे जोड़ दिया
eg- तमिलनाडु का 69% आरक्षण वाला मामला।

(घ) संवैधानिक सर्वोच्चता संविधान का बुनियादी भाग है ऐसे में विधायी सर्वोच्चता को 9 वी अनुसूची के रूप में रखना असंवैधानिक है।

हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष-2007 में अपने निर्णय में 9 वी अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं बताया तथा इसमें निहित अनुच्छेदों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है जो केशवानंद भारती वाद (1973) के बाद जोड़े गए है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

अतः 9वीं अनुसूची तात्कालिक समय में 'वितरण मूलक न्याय' सुनिश्चित करने एवं व्यापक भूमि सुधारों के लिए लायी गई लेकिन वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर पुनर्विचार समय की मांग है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Asymmetry is an important characteristic of federalism in India, which has helped in the accommodation of diverse demands inherent in our democracy. Discuss. **(250 words) 15**

असममिति भारत में संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसने हमारे लोकतंत्र में निहित विविध मांगों के समायोजन में सहायता प्रदान की है। चर्चा कीजिए।

असममिति से तात्पर्य संघवाद में विभिन्न इकाइयों के साथ अलग-अलग व्यवहार एवं शक्ति वितरण से है। अर्थात समान शक्तियों का बंटवारा न होकर भिन्न-भिन्न व विशेष व्यवस्था (जैसे) - 5 वीं एवं 6 अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान करना

भारतीय संघवाद में असममिति के प्रावधानों ने भारतीय लोकतंत्र की विविधतापूर्ण मांगों में सामंजस्य बनाया है। जैसे -

→(a) विशेष राज्य का दर्जा - संविधान में अनुच्छेद -371 में महाराष्ट्र एवं गुजरात के उत्तरा! विदर्भ, मराठवाड़ा एवं कच्छ सौराष्ट्र के लिए प्रावधान
- नागालैण्ड एवं मिजोरम हेतु विशेष प्रावधान
- राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में अलग

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अलग प्रावधान करना

(जैसे) – 239AA दिल्ली के लिए विशेष विधान सभा मंत्रिपरिषद का प्रावधान

(ख) 5 वी अनुसूची में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान
eg – पेसा एक्ट 1996.

(ग) 6 अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषदों का गठन करना

(घ) कश्मीर को अनु. 35(A) के तहत विशेष राज्य का दर्जा देना

इन असममिति प्रावधानों से संघ में भाषायी, क्षेत्रीय, धार्मिक एवं आर्थिक मांगों की पूर्ति के प्रयास किए गए जिसने हमारे लोकतंत्र को विघटन एवं विखण्डन से बचाए रखा।

चुनौतियाँ
→ सापेक्षिक वंचना की भावना
Eg- गोरखालैण्ड की माँग
→ तुष्टीकरण की राजनीति हुई
Eg- कश्मीर को धारा-370 देना
→ अन्य क्षेत्रों द्वारा माँग करना
Eg- आन्ध्र प्रदेश को विशेष पैकेज
→ संघवाद में पक्षपात, भेदभावमूलक

आगे की राह भारत के बहुल विविधताओं वाला संघवाद है अतः विविधता अनुसार संघवाद में असममिति होना उचित है लेकिन इसका राजनीतिकरण न हो।

—— x ——

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. In India, the Finance Commissions are established pursuant to the constitutional mandate. In this context, do you think the State Finance Commissions have been effective in promoting fiscal federalism? Substantiate with arguments. **(250 words) 15**

भारत में वित्त आयोगों की स्थापना संवैधानिक अधिदेश के अनुसार की जाती है। इस संदर्भ में, क्या आपको लगता है कि राज्य वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने में प्रभावी रहे हैं? तर्कों के साथ पुष्टि कीजिए।

भारत में 73वे, 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग - 9 जोड़ा गया जिसके अनुच्छेद - 243(I), 243(Y) में 'राज्य वित्त आयोग' की स्थापना के प्रावधान है।

राज्य वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद को बढ़ाने में भूमिका - निम्नानुसार रही

(क) राजकोषीय संघवाद से आशय राज्य के विभिन्न स्तरों पर आर्थिक सम्बंधों का निर्धारण - जैसे - राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के मध्य कर, राजस्व विभाजन के सिद्धान्त देता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

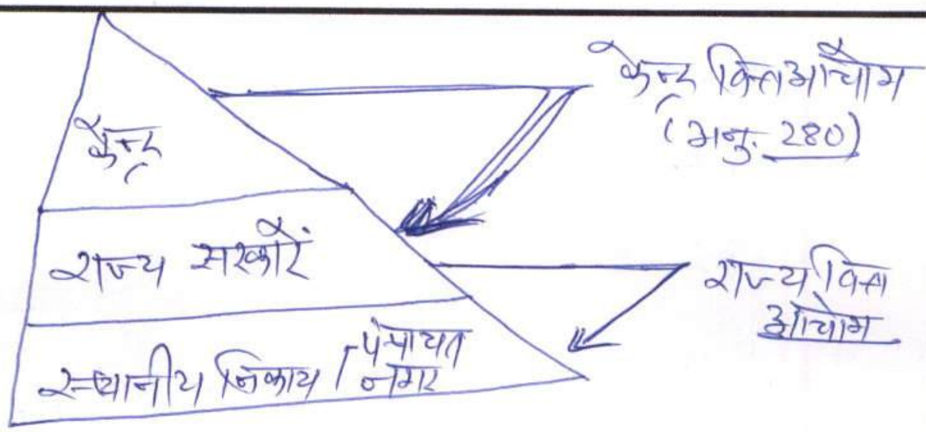

(ख) राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों के वित्त हस्तांतरण का पुल बनाता है। राज्यों की संवैधानिक दायित्व को रेखांकित करता है

चुनौतियाँ

* समय पर गठन नहीं होना
  eg- हर पाँच वर्ष के प्रावधान का उल्लंघन 'राजस्थान सरकार
* वित्त आयोग के सदस्य विशेषज्ञ न हो कर राजनीतिक नियुक्ति से
* राज्यों द्वारा वित्त आयोग की अनुशंसाओं की अनदेखी
* स्थानीय निकायों को बहुत कम वित्त हस्तांतरण

- राज्य वित्त आयोग के पास वित्त हस्तांतरण के सिद्धान्तों, नीतियों, फीडबैक, इनपुट सूचना का अभाव रहा अतः यह राजकोषीय संघवाद में अपनी भूमिका निर्वहन में कमतर साबित हो रहे है।

आगे की राह -> केन्द्र सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोगों के लिए एक व्यापक निर्देश पुस्तिका तैयार करना, राजनीतिकरण से मुक्त करना, स्थानीय निकायों को जागरूक करना

अतः राजकोषीय संघवाद में सरकार के तीसरे स्तर (स्थानीय निकायों) के सशक्तिकरण हेतु राज्य वित्त आयोगों को मजबूत करना होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Reduction in the overall size of the bureaucracy has been seen as the underlying idea behind civil services reforms. Is it a good idea to reduce the size of the Indian bureaucracy? Examine in light of the experience of India. **(250 words) 15**

नौकरशाही के समग्र आकार में कमी को सिविल सेवाओं में सुधार के पीछे अंतर्निहित विचार के रूप में देखा गया है। क्या भारतीय नौकरशाही के आकार को कम करना एक उपयुक्त विचार है? भारत के अनुभव के आलोक में परीक्षण कीजिए।

भारतीय नौकरशाही के विशाल आकार को देखते हुए (7 वें वेतन आयोग) ने इसे कम करने कि सिफारिश की थी।

(द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग) ने नौकरशाही की अक्षमता, गैर-कार्य कुशलता के कारणों में एक कारण इसका बड़ा आकार होना भी बताया है। जो करीब 2 करोड़ है।

आकार कम करने के पक्ष में तर्क

→(क) विशाल आकार के कारण वित्तिय बोझ होता

(ख) मिनीमम गवर्मेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के दौर (नव उदारवाद) के अनुकूल समय की मांग है।

(ग) आकार के अनुसार कुशल दक्षता नहीं है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

(घ) 'मिशन कर्मयोगी' के उद्देश्यों के अनुसार नौकरशाही को तकनीकी रूप से दक्ष, प्रशिक्षित एवं स्मार्ट होना चाहिए न कि भीड़ के रूप में।

(ङ) ई-गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस के दौर में नौकरशाही का कम, एवं प्रभावी होना जरूरी है।

विपक्ष में तर्क -> * भारत में प्रति एक लाख की आबादी पर मात्र 133 सरकारी कर्मचारी जबकि अमेरिका में 600 से अधिक है इसलिए पहले ही कम।

* विकासशील देश एवं कल्याणकारी राज्य की बढ़ती अपेक्षा (शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा) के लिए सरकारी मशीनरी आवश्यक है।

* बेरोजगारी, बढ़ती युवा आबादी के लिए सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सरकारी प्रयास - मिशन कर्मयोगी, निष्ठा प्रोग्राम स्मार्ट प्रोग्राम एवं ई-गवर्नेंस की योजनाएं लाकर सरकारी तंत्र को दक्ष बनाना।

आगे की राह - भारत के विकासशील देश है अतः नौकरशाही के आकार के साथ उसे दक्ष करने के उपाय करने चाहिए ताकि भ्रष्टाचार, लालफीताशाही एवं अक्रियता को दूर कर उत्पादकता बढ़ सके

———— × ————

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. There is a need to ensure better ethical standards, accountability and management of temples in India. Discuss in the context of issues associated with state intervention in management of temples. **(250 words) 15**

भारत में मंदिरों के बेहतर नैतिक मानकों, जवाबदेही और प्रबंधन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मंदिरों के प्रबंधन में राज्य के हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।

भारत के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है
तथा धार्मिक संस्थाओं का संचालन
अनु० 26 के तहत मूल अधिकार है
लेकिन भारत में सरकार द्वारा धार्मिक संचालन का
लम्बा इतिहास रहा है।
eg- मद्रास हिन्दु रिलीजस एक्ट

(मुद्दे) -> राज्य की धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ
-> धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित
-> धार्मिक ट्रस्टों में भ्रष्टाचार
eg- चढ़ावे का दुरुपयोग
-> आध्यात्मिक प्रक्रिया को कम बनवा देना

—) धार्मिक संगठनों (मंदिरों, मैठों) का राजनीतिकरण करना।

—) धर्म पदों पर स्थानीय राजनीति का चलन वातावरण को दूषित होना।

—) धार्मिक स्थलों के स्थ स्थान रोप अवसंरचना की खराब हालत है।

उपाय —> धार्मिक विभाग की जगह अलग संस्था बनाना।

—> केवल नियामक का कार्य करना तथा प्रबन्धन का कार्य जनता को देना।

—) स्थानीय स्तर पर चुनाव प्रणाली द्वारा मंदिर प्रशासन का संचालन

—) अवसंरचना विकास हेतु योजनाएं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जैसे → ओपन ए हेरीटेज स्कीम

आगे की राह - राज्य को धार्मिक संस्थाओं से मुक्त होने के लिए एक स्वतंत्र सेमी गोवर्मेंट संस्था बनाना। एवं उसमें सम्बंधित धर्म के प्रतिनिधियों को प्रबंधन का काम सौंपना

—— x ——

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. What do you understand by feminisation of old age? Highlight the issues associated with it in the Indian context. Also, mention the measures taken by the government in this regard. **(250 words) 15**

वृद्धावस्था के नारीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय संदर्भ में इससे जुड़े मुद्दों पर प्रकाश डालिए। साथ ही, इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख कीजिए।

वृद्धावस्था के नारीकरण से तात्पर्य वृद्ध जनसंख्या में महिलाओं का बढ़ता अनुपात। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत में वृद्धों का लिंगानुपात इस तरह बढ़ा —

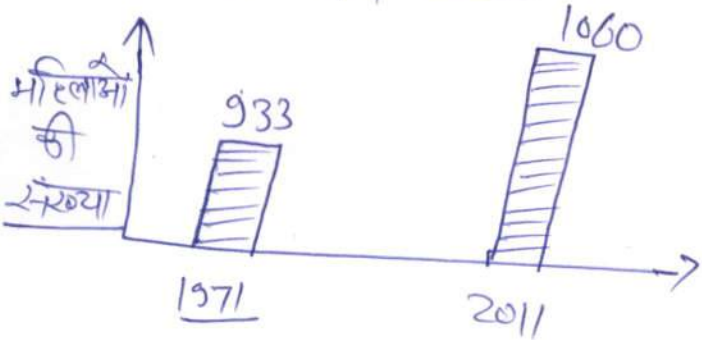

प्रमुख मुद्दे
1. वृद्धावस्था में पर निर्भरता
2. आर्थिक निर्भरता एवं परिवार द्वारा बोझ समझना
3. विधवाओं, परित्यक्ता की सामाजिक स्थिति शोषणकारी
4. देखभाल एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

⑤ वृद्धावस्था के नारीकरण के कारण बुढ़ापे में महिलाओं को स्वास्थ्य, वृद्धजन रोगों एवं भावनात्मक अकेलेपन का शिकार होना।

⑥ पुरुषों की तुलना में मात्र 10% महिलाऐं ही आर्थिक रूप से निर्भर होती है।

⑦ सामाजिक सुरक्षा (बीमा, पेंशन) का अभाव होता है।

सरकार के प्रयास

(क) प्रधानमंत्री वय वंदना योजना द्वारा बचत एवं पेंशन की स्कीम
(ख) इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना
(ग) वयोश्री योजना (पुरस्कार)
(घ) वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ाने की स्कीम
(ग) अन्त्योदय अन्न योजना।
(घ) राजस्थान की भामाशाह योजना

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

वृद्धावस्था का नारीकरण सामाजिक मनोस्थिति के विद्रूप स्थिति को दर्शाता है अतः महिलाओं के लिए NGO (जैसे- give India) के साथ मिलकर कल्याण कारी स्कीम की जरूरत है।

———×———

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Given its impact on both individual resilience and the resilience of the economy, is there a case for strong universal social protection in India? Discuss. **(250 words) 15**

व्यक्तिगत लचीलेपन और अर्थव्यवस्था की प्रत्यास्थता दोनों पर इसके प्रभाव को देखते हुए, क्या भारत में सुदृढ़ सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की स्थिति विद्यमान है? विवेचना कीजिए।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य सभी नागरिकों को बीमा, पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से है।

चुनौतियाँ

- 92% आबादी (श्रमबल) असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अतः उन्हें सामाजिक सुरक्षा देना चुनौतीपूर्ण है
- घरेलू कामगारों, बाल श्रमिकों एवं खेतिहर भूमिहीन वर्ग का डेटा एवं पहचान की चुनौती
- भारत का विशाल कार्यबल है अतः आर्थिक चुनौती

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

* कार्यबल का गैर-कुशल, प्रशिक्षित न होना।
* अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक स्वरूप होना

उपाय → सम्पूर्ण कार्यबल का डेटा तैयार करना। जैसे - ई-श्रम कार्ड

* ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड 27 करोड़ श्रमिकों को मृत्यु पर 2 लाख एवं विकलांगता पर 2 लाख का बीमा दिया
* जन-धन योजना एवं प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का क्रियान्वयन
* दिव्यांगजन, वृद्धजन, विधवाओं एवं सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा देना।
* युवा आबादी को कौशल-प्रशिक्षण देना

सरकारी प्रयास — (1) ई-श्रम पॉर्टल

(2) PM दुर्घटना बीमा योजना

(3) PM वय वंदना योजना

(4) इन्दिरा गांधी पेंशन योजना

(5) PM रोजगार प्रोत्साहन योजना

(6) स्किल इंडिया स्कीम

आगे की राह - अतः भारत को अपनी कार्यबल जनसंख्या का औपचारिकरण कर एवं आश्रित जनसंख्या को सार्वभौमिक सामाजिकरण लक्षित रूप से देना चाहिए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. There have been arguments that with the old global multilateral order failing to manage rising challenges, issue-based coalitions are gaining traction and have become the arenas of functional cooperation. Discuss. **(250 words) 15**

ऐसे तर्क दिए गए हैं कि पुरानी वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था बढ़ती चुनौतियों का प्रबंधन करने में विफल रही है, जबकि मुद्दे-आधारित गठबंधन लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं और कार्यात्मक सहयोग के क्षेत्र बन गए हैं। चर्चा कीजिए।

पुरानी वैश्विक बहुपक्षीय व्यवस्था वर्तमान के संकट eg- रूस-यूक्रेन संघर्ष, आर्मेनिया-अजरबैजान, 'अफगानिस्तान' तालिबान शासन, या म्यामार सैन्य' तख्तापलट जैसी समस्याओं के समाधान में असफल हुई है अतः अब विश्व मुद्दा आधारित संगठनों की तरफ बढ़ रहा है।

(कारण) (क) (संयुक्त राष्ट्र संघ) रूस रूस अमेरिका के विरोध का मंच बनकर रह गया। शक्तिहीन रूप फंड के लिए पश्चिमी देशों पर अतिनिर्भरता ने इसे पंगु बना दिया।

(ख) WTO, WHO एवं यूनेस्को की कार्यप्रणाली पक्षपातपूर्ण है।
eg- WHO द्वारा चीन पर बेरुखी

(ग) अमेरिका द्वारा ट्रेड वॉर, करेन्सी वॉर संरक्षणवादी कदमों के कारण

(घ) जलवायु कार्यवाहियों की असफलता
जैसे- पेरिस समझौता, ग्लासगो सम्मीट में केवल बातें।

मुद्दे आधारित गठबंधन की लोकप्रियता की वजह

↳ 1. भारत द्वारा सौर ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना एवं सदस्यों की बढ़ती संख्या।

2. RCEP जैसे क्षेत्रीय व्यापार संगठनों का बढ़ना।

3. आसियान जैसे क्षेत्रीय समझौतों की सफलता

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

७ न्यू डेवलेपमेन्ट, AIDB ने WB व IMF को चुनौती दी।

८ क्वाड का गठन हिन्द-प्रशांत के मुद्दे पर हुआ।

अतः हम कह सकते हैं कि अब बहुपक्षीय विश्व की बजाय देश मुद्दों व राष्ट्रीय हितों से प्रेरित हो रहे हैं

——— x ———

20. India intends to achieve a balanced and optimal development of energy infrastructure in the South-Asian region through mutual understanding and cooperation. In light of this statement, discuss the need as well as existing gaps in South Asia's energy cooperation. **(250 words) 15**

भारत पारस्परिक समझ और सहयोग के माध्यम से दक्षिण-एशियाई क्षेत्र में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे में एक संतुलन और उसका इष्टतम विकास सुनिश्चित करना चाहता है। इस कथन के आलोक में, दक्षिण एशिया में ऊर्जा सहयोग की आवश्यकता और इस संदर्भ में विद्यमान कमियों पर चर्चा कीजिए।

भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एवं श्रीलंका जैसे दक्षिण-एशियाई देशों की ऊर्जा सुरक्षा कुछ आयात के नियम आयात पर आधारित है। जो चिंता का सबब है।

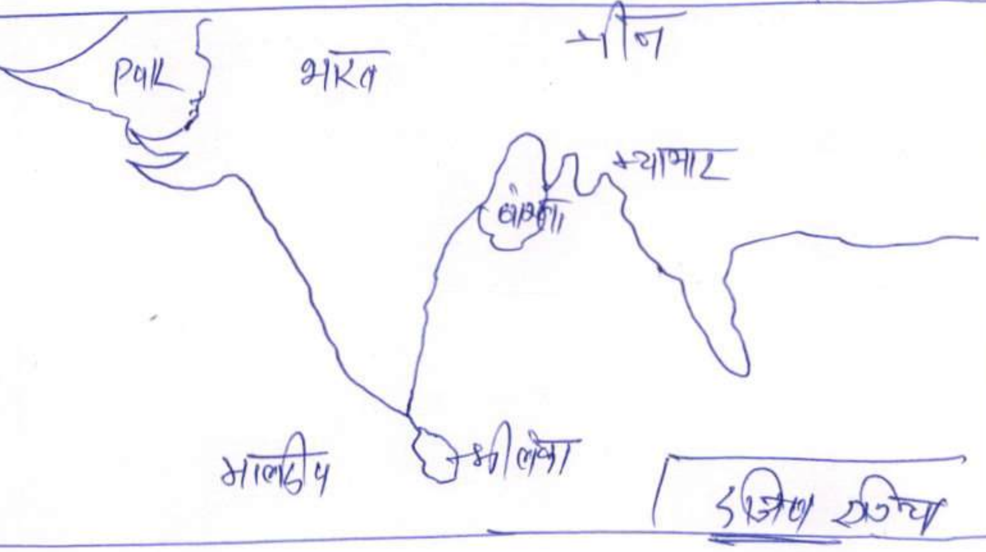

मुद्दे — ऊर्जा सुरक्षा आयात आधारित है
ex- भारत 85% आयात
- क्षेत्रीय सहयोग का अभाव
भारत- पाक विवाद

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

① संसाधनों की अनुपलब्धता
eg - तेल भंडार का अभाव

② Poor ~~connl~~ connectivity के कारण सहयोग नहीं
eg - TAPI परियोजना का लंबित होना

उपाय - ① नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा
eg - भारत द्वारा ISO बनाना

② आयात को कम करना

③ कनेक्टिविटी बढ़ाना
भारत → पाक → ईरान

④ निवेश को बढ़ाना

⑤ रिफाइनरी उद्योग को बढ़ाना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

आगे की राह - ऊर्जा सुरक्षा भविष्य में विकास की पहली शर्त है अतः ऊर्जा सुरक्षा को विकास हेतु कैसे सुनिश्चित करना।